सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष, 2018 के प्रथम सत्र में

डॉ0 कृष्ण कान्त पाल

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

भराडीसैंण, गैरसैंण (चमोली), मंगलवार, 20 मार्च, 2018 (29 फाल्गुन, शक सम्वत्, 1939)

सदस्यगण;

मैं आप सभी महानुभावों को वर्ष, 2018 के विधान सभा के प्रथम सत्र में हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए जिन मूलभूत चुनौतियों के समाधान व राज्य को उत्तरोत्तर विकास की ऊँचाईयों तक पहुँचाने के साथ–साथ स्वच्छ, पारदर्शी नीति को अपनाते हुए एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर अन्तिम व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य गठन के स्वप्न को साकार करने का प्रयास मेरी सरकार द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में किया गया है, उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्र सरकार की ओर से ऑल् वेदर रोड, एयर कनेक्टीविटी, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण, भारत माला परियोजना, कृषि सिंचाई योजना, नेशनल कैरियर सर्विस के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब सामूहिक रूप से आगामी वर्ष में भी राज्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

(1) **मेरी सरकार द्वारा वर्ष, 2017 में देश की आर्थिक आजादी के रूप में देखे जा रहे परिवर्तन** जी0एस0टी0 को लागू करने में अग्रणी भूमिका अदा की गयी है।

- पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी०एस०टी० में परिवर्तित किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,34,752 हो चुकी है।
- सरकार द्वारा व्यापारियों की सुविधा के लिए वैट के गत तीन वर्षों के वादों के स्वतः निस्तारण हेतु शासन डीम्ड स्कीम प्रख्यापित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वादों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।
- ब्लॉक स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर को जी0एस0टी0 सेवा केन्द्रों के रूप में सक्षम बनाकर तैयार किया गया है एवं राज्य भर से लगभग 1189 जी0एस0टी0 मित्रों को व्यापारियों की सहायता हेतु प्रशिक्षित किया गया है। इस पहल से न केवल युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त होगा वरन दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापारियों को सुविधा प्राप्त होगी।

- सरकार द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू करते हुए पंजीकृत व्यापारियों की आकस्मिक मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को ₹ पाँच लाख तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- सरकार द्वारा जी0एस0टी0 से सम्बन्धित तात्कालिक महत्व वाली सभी जानकारियाँ लगातार प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापारियों को दी जा रही है।
- स्टॉक होल्डर्स के प्रशिक्षण हेतु राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में पाँच सौ कार्यशालाएँ आयोजित कर व्यापारियों को जागरूक किया गया है एवं 27031 हित धारकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा सतत् रूप से प्रचार माध्यमों से व्यापारियों एवं जन सामान्य को जागरूक किया जा रहा है।
- सरकार द्वारा राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उददेश्य से प्रदेश के 50 उप–निबंधक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और जनसामान्य की सुविधा हेतु राज्य में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन के अन्तर्गत उप निबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत होने वाले विक्रय विलेखों को दाखिल खारिज हेतु ऑनलाइन के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलों को प्रेषित किये जाने हेतु राजस्व विभाग से संयोजन कराये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।
- सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों हेतु सटीक रणनीति बनाने में यू0एन0डी0पी0 की विशेषता का लाभ प्राप्त किया गया है। सहभागिता कार्यक्रम प्रारम्भ कर प्रथम चरण में उद्यान एवं पर्यटन विभाग के कार्मिकों को इसके अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।
- नीति आयोग की राज्य विकास समर्थक सेवा योजना के लिए राज्य की बारह योजनाओं के संकल्प पत्र नीति आयोग को प्रस्तुत किये गये हैं।
- हिमालयी राज्यों की विशिष्ट समस्याओं के आलोक में पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ सतत् विकास की ठोस रणनीति के तहत जन संवाद प्रारम्भ करते हुए हिमालय दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।
- वर्तमान में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है एवं राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है।

(2) मेरी सरकार द्वारा प्रशासनिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही व जन सामान्य के लिए उत्तरदायी बनाने एवं प्रशासनिक इकाईयों का विकेन्द्रीकरण कर छोटी प्रशासनिक इकाईयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

- विभिन्न महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल मार्ग तथा रुड़की–देवबंद रेल मार्ग का कार्य प्रगति पर है।
- डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन योजना के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। खतौनियों को देव भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन किया गया है।

(3) मेरी सरकार द्वारा लोक सेवकों के लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी स्थानान्तरण नीति बनाई गई है।

- राज्य सेवा के अधिकारियों हेतु विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।
- राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के द्वारा नियमित भर्ती की जा रही हैं।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अधियाचनों में से छः हजार चार सौ पचास पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्तियाँ जारी की जा चुकी हैं।
- एक हजार एक सौ पिचहत्तर पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

(4) मेरी सरकार राज्य के युवा वर्ग में विज्ञान लोकव्यापीकरण द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है।

- सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु उद्यमिता विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य कर रही है।
- राज्य में एक अत्याधुनिक साइंस सिटी की स्थापना के साथ–साथ बच्चों को प्रकृति में छिपे वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के साथ–साथ वैज्ञानिक सिद्धान्तों से भी परिचित कराने के उद्देश्य से विज्ञान धाम परियोजना के अन्तर्गत तारामण्डल एवं प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- मेरी सरकार 'डिजिटल इण्डिया' की भावनाओं के अनुरूप यूसर्क द्वारा उत्तराखण्ड के दूरस्थ विद्यालयों तक विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु 'प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा' का कार्य कर रही है।

- डिजिटल तकनीकी के जानकार, विशेषज्ञों, डिजिटल वॉलेन्टियर एवं तकनीशियनों को तैयार किया जा रहा है तथा राज्य में आम जनमानस को विज्ञान के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करने हेतु साइंस वॉलेन्टियर तैयार किये गये हैं।
- यूसर्क में स्थापित स्टूडियो में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों पर विषय विशेषज्ञों के ई–कन्टेन्ट हेतु व्याख्यान आयोजित किये जा रहे हैं।
- यूसर्क द्वारा विभिन्न विषयों के ई–सामग्री का समावेश करते हुए ज्ञान कोष पोर्टल का विकास किया गया है। पिछड़े वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने, क्षमता वृद्धि, भविष्य निर्धारण एवं विभिन्न विषयों की ई–सामग्री हेतु यूसर्क द्वारा 'मेन्टरशिप पोर्टल' का विकास किया गया है, जिसमें विद्यार्थी (मेन्टीस) एवं विशेषज्ञ (मेन्टर्स) द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
- 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम की भावना के अनुरूप छात्र–छात्राओं से अभिनव विचारों को प्राप्त करने एवं विलक्षण बच्चों की खोज हेतु 'अभिनव एवं रचनात्मक प्रतिभा खोज कार्यक्रम' चलाया जा रहा है।

(5) **मेरी सरकार समाधान पोर्टल के अन्तर्गत स्मार्ट आई0वी0आर0 सिस्टम के माध्यम से** मोबाइल/दूरभाष पर शिकायतें प्राप्त कर उनका निस्तारण किये जाने हेतु टोल फ्री दूरभाष नम्बर हेतु 1905 सेवा का शुभारम्भ कर आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर रही है।

- सरकार द्वारा शासन की छवि को स्वच्छ बनाये जाने हेतु भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है तथा भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है।
- सरकार द्वारा जन सामान्य की सुविधा की दृष्टि से अठ्ठारह विभागों की एक सौ साठ सेवाओं को सेवा के अधिकार में अधिसूचित किया गया है।
- राज्य में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। राज्य में सामुदायिक सद्भावना एवं नागरिकों में सुरक्षा भावना कायम करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
- पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार से ₹ छः सौ बासठ करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे सूचना तंत्र को मजबूत करने, नेशनल इमरजेन्सी दूरभाष नम्बर स्थापित करने एवं सिंगल इमरजेन्सी नम्बर स्थापित करने के कार्य किये गये हैं।

- अपराधों के प्रभावी नियंत्रण हेतु राजस्व पुलिस क्षेत्रों में दो नवसृजित पुलिस थाना एवं एक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित की गई है।
- पुलिस द्वारा "ऑपरेशन इस्माईल" चलाते हुए गुमशुदा बालक/बालिकाओं को बरामद करने के पश्चात् उनको उनके परिवार के सुपुर्द किया गया।
- पुलिस कार्मिकों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु आवासीय एवं अनावसीय भवनों का कार्य प्रगति पर है।
- पुलिस थानों के कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से पुलिस थाना विविध निधि में ₹ तीन करोड़ प्रतिवर्ष दिया जा रहा है।
- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के भवन हस्तांतरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। होमगार्ड स्वयंसेवकों का ₹ पाँच लाख का दुर्घटना बीमा कराया गया है। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में बदलाव कर आपदा राहत, यातायात नियन्त्रण आदि हेतु समुचित प्रयास किया जा रहा है।

(6) मेरी सरकार द्वारा आपदा से सफलतापूर्वक बचाव के लिये,

- भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु अभियन्ताओं व राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार संचालित करने,
- पूर्व निर्मित भवनों को भूकम्प सुरक्षित बनाये जाने हेतु रेट्रोफिटिंग का कार्य एवं आई0आई0टी0 रुड़की के सहयोग से राज्य में भूकम्प पूर्व चेतावनी यंत्र की स्थापना करने,
- आपदा की स्थिति में त्वरित संचार की व्यवस्था के लिए तीस नये सैटेलाइट फोन क्रय करते हुए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति विकसित किये जाने एवं आपदा की स्थिति में त्वरित व प्रशिक्षित प्रतिवादन हेतु राज्य आपदा प्रतिवादन बल को अत्याधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों से सुसज्जित किये जाने,
- प्राकृतिक आपदाओं के बचाव की जानकारी जन जागरण हेतु यूसर्क द्वारा 'साइंस ऑफ सरवाइवल' कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम संचालित किये जाने, का कार्य किया गया है।

(7) **मेरी सरकार सिंचाई से कृषकों को अपेक्षित लाभ दिये जाने हेतु प्रयत्नशील है।**

- वाटर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट गठित कर बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव विश्व बैंक को वित्त पोषण हेतु भेजा गया है।
- रिस्पना नदी, कोसी नदी व नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। आराकोट त्यूनी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्यवाही गतिमान है।
- सोलर पावर प्रोजेक्ट परियोजनाओं पर कार्यवाही गतिमान है। नलकूप, सिंचाई, लघुडाल नहरों के संचालन हेतु 40 मेगावाट सोलर पावर का उपयोग किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक एवं अभिनव तकनीकों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया गया है। असिंचित कृषि भूमि, कृषि योग्य क्षेत्रांक में लिफ्ट योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।
- कोसी बैराज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्षा का जल संग्रहण कर जल का उपयोग किया जा रहा है।
- बहुप्रतीक्षित जमरानी बाँध का उत्तर प्रदेश राज्य से एम0ओ0यू0 किया जा चुका है। अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
- देहरादून शहर के पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति एवं अण्डरग्राउण्ड वाटर रीचार्ज करने हेतु सौंग बाँध का निर्माण किया जायेगा।
- नैनीताल झील के पुनर्जीवीकरण हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।
- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत 101 किमी0 सिंचाई गूल, 322 सिंचाई हौज, 2 हाईड्रैम, आर्टीजन कूप तथा पम्प सेटों का निर्माण किया गया है।

(8) **मेरी सरकार द्वारा पारदर्शी आबकारी नीति के अन्तर्गत जिले के स्थाई निवासियों को ही दुकानें** आवंटित करने एवं स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिससे एक हजार सात सौ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है।

(9) **सरकार द्वारा राज्य स्तर पर उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के दृष्टिगत राज्य के दुर्गम** एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जनसामान्य को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर की उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

- चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु चिकित्सा अधिकारियों के लगभग छः सौ रिक्त पदों पर पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्ति की गयी है तथा चार सौ इक्यासी चिकित्सकों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।
- प्रत्येक मंगलवार को वॉक–इन इन्टरव्यू के माध्यम से भी संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्ति प्रदान किये जाने के प्रयास किये गये हैं।
- यू0 हैल्थ योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने के दृष्टिगत सोसाइटी गठन की प्रक्रिया गतिमान है। इस योजना के क्रियान्वित होने से लगभग दो लाख सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- सरकार द्वारा जन्म/मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्र तथा परिवार रजिस्टर पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है। इस हेतु सभी जिलों में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
- 62 नई एम्बुलेन्स उपलब्ध कराई गयी हैं।
- प्रत्येक जिला अस्पताल में आई0सी0यू0 खोले जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सको की उपलब्धता हेतु अतिविशिष्ट चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हुए 924 शिविरों का आयोजन किया गया।

(10) मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य योजना के अन्तर्गत परिवारों को चयनित करते हुए तेरह लाख तीन हजार राशन कार्डों को ऑनलाइन किया गया है। पिचानवे प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से लिंक कर लिया गया है।

- राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की कैश डी0बी0टी0 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की गई है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक लाख बत्तीस हजार परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं एवं शेष एक लाख दस हजार परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(11) सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का सम्पादन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता, कार्यपूर्ति आदि के लिए विभिन्न अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है।

- सरकार ने पंचायतों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करते हुए ग्राम पंचायतो में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए "डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" नाम देकर अभिनव प्रयास किया है।
- ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत के लिए वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाऐं स्वयं ग्राम सभा की खुली बैठकों में तैयार करने, स्थायी प्रकार की परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं जलापूर्ति, सीवरेज, सैप्टैज प्रबन्धन, जल निकासी, स्ट्रीट लाईट, सड़कों, फुटपाथों पर लगाये जाने तथा सरकार की प्राथमिकता वाली योजना पर विचार ग्राम स्तर पर किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को पर्याप्त धनाबंटन किया गया है। इस राशि का उपयोग जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सैप्टेज प्रबन्धन सहित जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव, स्ट्रीट लाईट, आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, सामुदायिक भवन निर्माण आदि पर किया जायेगा।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना के अन्तर्गत गत वर्ष सात उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इस वर्ष पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट चयन की प्रक्रिया गतिमान है।
- नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के अन्तर्गत उत्कृष्ट पंचायत के रूप में ग्राम पंचायत कुकरेड़ा जिला उत्तरकाशी को दस लाख का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, के तहत ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने, बी.पी.एल. परिवारों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मेरा गांव मेरी सड़क योजना सफलता पूर्वक संचालित कर रही है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ₹ एक हजार दो सौ छिहत्तर लाख व्यय करते हुए गरीब परिवार की महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु चार हजार चार सौ छियासी स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं पुनर्गठन किया गया है तथा दो हजार आठ सौ उन्नीस समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया है।

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में आतिथि तक कुल एक सौ सत्तर लाख मानव दिवसों का सृजन करते हुए ₹ पैंसठ हजार चार सौ पचास लाख की धनराशि व्यय की गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पर्वतीय राज्य हेतु प्रति आवास ₹ एक लाख तीस हजार अनुदान की धनराशि प्रदान की जा रही है।
- महिला स्वयं सहायता समूहों (महिला मंगल दल) के माध्यम से भी कम्यूनिटी कॉन्ट्रैक्टिंग के अन्तर्गत मार्गों के अनुरक्षण की अभिनव पहल की गई है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी वाले ऐसे क्षेत्र, जिनका तेजी से शहरीकरण हो रहा है एवं आबादी बढ़ रही है, का चयन क्लस्टर के रूप में करते हुए इन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

(12) सरकार पन्द्रह हजार आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पाँच हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर टेक होम राशन तथा प्रतिदिन स्कूल में उपस्थित होने वाले तीन से छः वर्ष के बच्चों को "मार्निग स्नैक्स" एवं ताजा पका भोजन उपलब्ध करा रही है।

- मेरी सरकार ने कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" तथा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए राज्य सहायतित "निर्भया योजना" समस्त जिलों में क्रियान्वित की है।
- कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, लिंग भेदभाव को हतोत्साहित करने हेतु "प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना" लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।
- सरकार द्वारा स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार को अधिक सुदृढ़ किये जाने पर बल दिया गया है।
- मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अन्तर्गत निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिला एवं किशोरी को सीड अनुदान एवं प्रशिक्षण छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- महिला स्वयं सहायता समूहो को स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाये रखने के उद्देश्य से "आदिभोग योजना" प्रारम्भ की जा रही है।

- "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" के अन्तर्गत लैंगिक भेदभाव के आधार पर शिशु जन्म को चयनित करने से रोकने, बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाने एवं बालिकाओं की शिक्षा, उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करते हुए हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता हेतु वूमेन हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(13) वर्तमान में राज्य में ग्यारह राज्य विश्वविद्यालय एवं अठ्ठारह अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क बीमा योजना का भी शुभारम्भ किया जा चुका है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर महाविद्यालयों को हस्तान्तरित किये जाने का कार्य और विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में बीस नये भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

- सरकार ने बाईस राजकीय महाविद्यालयों में नैक प्रत्यायन की कार्यवाही गतिमान की है और तीन राजकीय महाविद्यालयों द्वारा नैक प्रत्यायन कराया जा चुका है।
- रूसा योजना के अन्तर्गत पैंतीस महाविद्यालयों तथा तीन विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं एवं निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। संस्कृत भाषा में आधारित पाठयक्रम व यू0जी0सी0 के नये दिशा निर्देशानुसार साइबर सिक्यूरिटी पर आधारित पाठयक्रम इस शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ किये जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालय परिसर में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों के चित्रों से युक्त शौर्य दीवार का निर्माण किया गया है।
- कुमाऊँ विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय तथा मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में फ्री वाई–फाई सुविधा दी गयी है।
- सरकार द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा बारह तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को आगामी शैक्षिक सत्र में एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकें लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- आगामी शैक्षिक सत्र से कक्षा तीन व कक्षा छः में विज्ञान विषय को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाये जाने एवं आर0टी0ई0 मानक के अनुसार एक किलोमीटर के अन्तर्गत संचालित दस से कम छात्र संख्या वाले चार सौ पचास राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा तीन किलोमीटर के अन्तर्गत संचालित एक सौ पचास उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विलीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- विकास खण्डों में क्रमवार आवासीय विद्यालय खोले जाने, राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति के बैकलॉग हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष तैंतीस पद एवं सामान्य पदों की विज्ञप्ति के सापेक्ष चार सौ छब्बीस पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है।
- सरकार दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में जन–जन तक शिक्षा के प्रसार हेतु संकल्पबद्ध है।
- परिषदीय परीक्षाओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को गवर्नर्स एवार्ड से सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक कैरियर एवं वैयक्तिक मार्गदर्शन तथा निर्देशन हेतु बाल–सखा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
- बच्चों में आयरन की कमी को देखते हुए मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत राज्य के नौ सौ इक्तीस प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लोहे की कढ़ाई उपलब्ध करायी गयी है तथा भविष्य में समस्त विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए विकासखण्डों में आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- सभी राजकीय विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किये जाने एवं बच्चों में पढ़ने की आदतों को विकसित किये जाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एस0एस0ए0–पैसिफिक दून बुक बैंक की शुरूआत की गयी है।
- उत्तराखण्ड राज्य में छात्र–छात्राओं एवं युवाओं हेतु कौशल विकास अर्जन तथा उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि के उद्देश्य से राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षणों के साथ–साथ विभिन्न संस्थानों में इंजीनियरिंग तथा नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- विभिन्न उद्योगों/औद्योगिक संगठनों की सीएसआर गतिविधियों को प्रशिक्षण हित में उपयोग किये जाने के दृष्टिगत हल्द्वानी एवं देहरादून के विभिन्न संस्थानों में रोजगारपरक कोर्स प्रारम्भ करने हेतु विभिन्न कम्पनियों के साथ एम0ओ0यू0 किये गये हैं तथा अन्य कम्पनियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

- मेरी सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने के दृष्टिगत आधुनिक प्लम्बर तकनीक में प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला आयोजित करायी गयी। छः आई0टी0आई0 संस्थानों में प्लंबिंग लैब स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- राज्य में प्रथम बार नवीन सेक्टरों के अन्तर्गत प्लास्टिक प्रोसेसिंग, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, सॉयल टेस्टिंग एवं क्रॉप असिस्टेंट कोर्स प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- विश्व बैंक के सहयोग से रोजगारपरक प्रचलित व्यवसायों को संचालित करने, स्थानीय स्तर पर व्यवसायों के निर्धारण, प्रशिक्षार्थी व अनुदेशकों के ऑन/ऑफ द जॉब प्रशिक्षण तथा उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं में अधिकतम क्षमता परिवर्धन हेतु ₹ पाँच सौ करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्यवाही गतिमान है। योजना में चिन्हित 25 संस्थानों के विकास हेतु प्रोफेशनल फर्म द्वारा संस्थान की विस्तृत योजना बनाई जा रही है।
- उद्योगों में सीधे रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य में संचालित निजी उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्रयोगात्मक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। विभिन्न कम्पनियों के सहयोग से 301 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- परीक्षा प्रणाली में गुणवत्ता लाने के लिए परीक्षा परिषद् में डीजीटी के अनुरूप परीक्षाओं को ऑनलाइन किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- शिल्पकार प्रशिक्षण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹ नौ लाख छियानवे हजार की धनराशि प्राविधानित है। उक्त धनराशि से विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीवीटी/एससीवीटी के अन्तर्गत संचालित व मूल्यांकित किये जा रहे हैं।
- कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत रोजगारोन्मुख अल्प कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।
- सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। विद्यार्थियों हेतु नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये हैं।
- सरकार संस्कृत विश्वविद्यालयों में परम्परागत उपाधियों के साथ-साथ कर्मकाण्ड, ज्योतिष, योग, वास्तुशास्त्र, पत्रकारिता आदि में प्रमाण पत्र देने एवं पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है।

(14) मेरी सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। उर्दू अकादमी एवं पंजाबी अकादमी द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है।

(15) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग एक हजार एक सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण, लगभग सात लाख फल पौध वितरण, पैंतालीस लाख सब्जी पौध वितरण, नौ सौ कुन्तल सब्जी बीज वितरण, एक सौ पैंतालीस कुन्तल आलू बीज वितरण, दो हजार चार सौ कुन्तल अदरख बीज वितरण किया गया है तथा चार हजार व्यक्तियों को औद्यानिक संयत्र वितरित किये गये हैं।

- सरकार मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्यान कार्ड वितरण किये जाने, फसल बीमा योजना लागू करने, और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की योजना को बढावा दिये जाने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान दिये जाने का कार्य कर रही है।
- संकल्प से सिद्धि योजना के अन्तर्गत कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की दिशा में सरकार द्वारा कृषक समृद्धि यात्रा का शुभारम्भ कर दिया गया है, जिसमें कृषि एवं उद्यान तथा अन्य रेखीय विभागों को सम्मिलित कर माइक्रो प्लानिंग प्रारम्भ कर दी गयी है।
- सरकार जिला पिथौरागढ़, चमोली व रूद्रप्रयाग के उच्च शिखरीय क्षेत्रों में औषधीय पादपों के संकुल आधारित कृषिकरण को प्रोत्साहित कर रही है।
- "अटल जड़ी–बूटी मिशन" योजना की राज्य में शुरूआत की गयी है, जिसंमें कुटकी प्रजाति का वृहद स्तर पर कृषिकरण कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे कृषकों की आय में दो गुना वृद्धि होगी।

(16) राज्य के युवाओं को रोजगार देने एवं परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत चार सौ चौबीस संविदा परिचालकों की भर्ती परीक्षा करायी जा चुकी है। नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

- विशेष श्रेणी/संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को देय मजदूरी में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गयी है।
- राज्य के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं हो रहा था उन क्षेत्रों में बस सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

- विभिन्न राजमार्गों पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर आर0एफ0आई0डी0 युक्त फास्ट टैग के माध्यम से कैशलैस भुगतान किया जा रहा है।
- राज्य गठन के बाद दोनों राज्यों के मध्य बसों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के साथ परिवहन करार सम्पन्न किया गया है।
- पायलट परियोजना के रूप में प्रदेश के सभी कार्यालयों में ऑनलाइन डीलर प्वाईंट डाटा एन्ट्री/कर भुगतान की सुविधा प्रारम्भ की गयी है।

(17) मेरी सरकार ने छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र–छात्राओं, जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा से दोगुना से अधिक न हो, को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु सरकारी नौकरी एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम पिचहत्तर हजार की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।
- मेरी सरकार मदरसों की स्थिति सुधारने का कार्य कर रही है, जिनमें दीनी शिक्षा के साथ ही आधुनिक विषय यथा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि पढ़ाने की व्यवस्था होगी। इन आधुनिक विषयों को पढ़ाने वाले स्नातक अध्यापक को छः हजार तथा परास्नातक एवं बी.एड. को बारह हजार की दर से मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
- सरकार की पहली प्राथमिकता समाज के कमजोर वर्ग का उत्थान करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओं हेतु बजट की पृथक व्यवस्था की गई है, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में अठानवे हजार छात्रों को लाभान्वित करते हुए दस करोड़ पचास लाख की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप से वितरित की गई है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा में अभिरूचि विकसित करने एवं शैक्षिक विकास के उद्देश्य से आश्रम पद्धति विद्यालय एवं आदर्श आवासीय

विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अध्ययन सामग्री, आवास, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं।

- रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा दिये जाने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में छः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आठ सौ सैंतालिस परिवारों को उनकी पुत्री के विवाह हेतु ₹ पचास हजार प्रति परिवार अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है।
- अटल आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चार सौ चौसठ परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- पिछड़ी जाति के कल्याण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन हजार पैंतालीस छात्र–छात्राओं को ₹ अड़तालीस लाख बहत्तर हजार की छात्रवृत्ति प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।
- दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित करते हुए रोजगारपरक व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक सौ छब्बीस निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र प्रदान कर उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।
- मेरी सरकार द्वारा निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, के वितरण से छः लाख पाँच हजार पाँच सौ पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।
- साठ वर्ष से अधिक आयु वाले कृषकों को प्रतिमाह पेंशन देकर पन्द्रह हजार तीन सौ छियासठ कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों को विवाह हेतु ₹ पचास हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
- एकीकृत विकास, जनजाति विकास परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। दून विश्वविद्यालय परिसर में जनजाति शोध संस्थान की स्थापना की गई है।
- मेरी सरकार राज्य के पूर्व सैनिकों, शहीदों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराने, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें लाभ दिलाने एवं पुनर्वास तथा पुनर्योजन कराने के लिए संकल्पबद्ध है।

- सरकार राज्य पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के अधिष्ठान में आने वाले व्यय का दो तिहाई तथा सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण में आने वाले व्यय का पचास प्रतिशत अंश वहन कर रही है।
- वीरता पदक विजेताओं को शासन द्वारा देय एक मुश्त एवं वार्षिकी में अभूतपूर्व वृद्धि की गयी है तथा वार्षिकी जो पूर्व में तीस वर्षो तक के लिए अनुमन्य थी उसे आजीवन क़र दिया गया है। इस क्रम में उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर व विधवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रतिमाह पेंशन/अनुदान का भुगतान किया जा रहा है।
- विभिन्न युद्धों/सीमान्त झड़पों में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं/ माता–पिता एवं निःशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क टोल फ्री नम्बर बातचीत हेतु उपलब्ध कराया गया है।
- सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, आवास, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है।
- सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/ आश्रितों को एक मुश्त अनुग्रह अनुदान ₹ बारह लाख की धनराशि अनुमन्य करायी जा रही है।
- राज्य के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/सैन्य कार्मिकों को गृहकर में छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है ।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों की पेंशन ₹ चार हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ आठ हजार प्रतिमाह की गयी है।

(18) **सरकार द्वारा विभिन्न खेलों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन** हेतु कई लाभकारी योजनाएं संचालित करायी जा रही हैं।

- राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, विस्तारीकरण के अन्तर्गत हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तथा देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स का निर्माण कराया जा रहा है।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं को खेल की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जा रही हैं।
- राज्य के खिलाड़ियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने के दृष्टिगत देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं।
- सरकार द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को विभिन्न शासकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/ निगमों तथा उपक्रमों में शान्ति सुरक्षा व्यवस्था के अलावा डाटाएन्ट्री कार्य, वाहन चालक, अनुसेवक आदि कार्यों हेतु तैनात किया गया है। इसमें लगभग चार हजार पाँच सौ से अधिक स्वयंसेवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- सरकार खेलों के उत्थान हेतु प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान/खेल अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- शूटिंग की सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से शूटिंग रेंज का निर्माण महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में इंडोर बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खिलाड़ियों को इंडोर खेल की सुविधाएँ प्रदान कराते हुए वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।
- राज्य के प्रत्येक जिले में खेल प्रशिक्षण शिविर एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 2390 खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं।
- खिलाड़ियों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये जाने के साथ ही विशिष्ट खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किये जा रहे हैं।

- अल्मोड़ा में शूटिंग संस्थान एवं बैडमिंटन के लिए आधुनिक स्टेडियम निर्माण का निर्णय लिया गया है।

(19) मेरी सरकार सांस्कृतिक धरोहर एवं संरक्षण–संवर्द्धन तथा सर्वांगीण विकास के लिए नृत्य, नाटक एवं लोक संगीत, आदि का विकास तथा व्यापक प्रचार–प्रसार, पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण व अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर कार्यों के सम्पादन हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

- पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव, वीरौंखाल में जन्मी वीरांगना तीलू रौतैली के नाम पर उनके पैतृक जन्मस्थल वीरौंखाल में उनके शौर्य एवं संघर्ष से जुड़ी वर्णित घटनाओं को संग्रहीत किये जाने हेतु संग्रहालय स्थापित किया जायेगा।
- देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रपुर में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
- राज्य स्तरीय प्रेक्षागृह (हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र), गढ़ी कैन्ट, देहरादून का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे समयबद्ध रुप से पूर्ण किया जायेगा।
- मेरी सरकार द्वारा दीर्घकालीन पर्यटन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 13 डेस्टीनेशन विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। नये पर्यटन गन्तव्यों में पर्यटन की दृष्टि से अवस्थापना सुविधाएं विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रसाद योजना के अन्तर्गत बद्रीनाथ में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ₹ छप्पन करोड़ की प्रस्तावित योजना पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है।
- स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत ₹ अठानवे करोड़ की योजनाएं प्रस्तावित कर कन्सेप्ट नोट भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रेषित किया गया है।
- केदारनाथ धाम के सुनियोजित विकास हेतु विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य गतिमान है।
- पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना का कार्य गतिमान है।

- "अतिथि–उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना" के अन्तर्गत दो सौ अड़सठ आवासीय इकाईयां पंजीकृत की जा चुकी हैं। विजन 2020 के अन्तर्गत पाँच हजार होम स्टे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" का दायरा बढ़ाते हुये इसमें अन्य पर्यटन व्यवसायों यथा टेराइन बाइक्स के संचालन, कैरेवन टूरिज्म के विकास, एंगलिंग उपकरणों के क्रय, स्टार गेजिंग हेतु उपकरणों के क्रय, आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटन सूचना केन्द्र, लॉण्ड्री की स्थापना, बेकरी की स्थापना, फूड प्रोसेसिंग की इकाई स्थापित करने तथा मैमोराबिलिया आदि को भी शामिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- कद्दूखाल से सुरकुण्डा देवी तथा ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी के रोप–वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। जानकी चट्टी–यमुनोत्री, घांघरिया–हेमकुण्ड रोप–वे की निर्माण प्रक्रिया गतिमान है।
- राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय मातृ–पितृ तीर्थाटन योजना में नये धार्मिक स्थलों ताड़केश्वर, कालीमठ, जागेश्वर, गैराड़ गोलू, गंगोलीहाट तथा बैजनाथ को सम्मिलित किया गया है।
- प्रदेश में पर्यटकों के मार्ग दर्शन एवं पर्यटक स्थलों की समुचित जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुये सत्तानवे युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये गये हैं।
- रिवर राफ्टिंग में राज्य को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल में बारह शक्ति पीठों को विकसित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में भगवान शिव, भगवान विष्णु, नागराज देवता व गोलू देवता के स्थलों को विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- कलनरी टूरिज्म को बढ़ावा देते हुये स्थानीय व्यंजनों को परोसा जायेगा, जिससे देश–विदेश के पर्यटक भी इस ओर आकर्षित होंगे तथा स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।
- हरिद्वार में अखाड़ा दर्शन, देहरादून में दून दर्शन, पौड़ी दर्शन, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा दर्शन एवं नैनीताल में अन्य झीलों के दर्शन हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के माध्यम से टूर पैकेज संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

- सरकार द्वारा सतपुली झील, खैरासैंण तथा ल्वाली झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने के साथ–साथ ऊधमसिंहनगर में बौर जलाशय को जल क्रीड़ा हेतु विकसित किया जा रहा है।

(20) मेरी सरकार नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन–जन तक पहुँचाने का कार्य तत्परता से कर रही है।

- मेरी सरकार ने पत्रकारों हेतु पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधा एवं राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है।
- प्रेस क्लबों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए भी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है तथा लघु एवं मझोले समाचार–पत्र/पत्रिकाओं के उत्थान के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(21) सरकार द्वारा राज्य परियोजनाओं/कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की स्थापना की गयी है। जिसके अंतर्गत सम्बन्धित को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- मेरी सरकार ने भारत सरकार की संस्थाओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी भवन में राज्य ड्रोन पर शोध एवं प्रशिक्षण तथा साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण हेतु नेशनल टेक्निकल रिसर्च आरगेनाइजेशन तथा नेशनल क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेन्टर के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया है।
- राष्ट्रीय सूचना अवस्थापना की पायलट परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जिला हरिद्वार में हॉरिजेन्टल कार्यालयों सहित कनेक्टीविटी के अन्तर्गत नब्बे ग्राम पचांयतो को संयोजित कर दिया गया है।
- नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्र सेवायोजन केन्द्र तथा कार्यशील कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल को तैयार करके आगामी वर्ष तक लगभग एक सौ सेवाएं प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर पोर्टल के माध्यम से सभी राजकीय भुगतान ऑनलाइन किये जा रहें हैं।

- ई–गवर्नेन्स व डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही है और अद्यतन चार हजार दो सौ सतहत्तर कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(22) **भेड़ पालन सीमान्त पर्वतीय जिलों में एक सकारात्मक व्यवसाय है। इस हेतु मेरी सरकार ने** ऊन बैंक की स्थापना की है। राज्य स्तर पर भेड़ की ऊन का न्यूनतम् सर्मथन मूल्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया जा रहा है।

- मेरी सरकार राज्य में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दे रही है। नौ क्लस्टर केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं एवं वर्तमान बाजार माँग के अनुसार खादी के वस्त्रों पर नये–नये डिजाइनो का समावेश करने हेतु डिजाइनरों का सहयोग लिया जा रहा है।
- पर्वतीय जिलों में प्राकृतिक रेशा जैसे डास कंडाली, भीमल एवं रामबॉस पर आधारित पारम्परिक कास्तकारों (दस्तकारों) को संरक्षित कर रोजगार की सम्भावनाओं के दृष्टिगत् रेशा क्रय योजना संचालित की गयी है। प्राकृतिक रेशा क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक दस कुन्तल रेशा क्रय किया जा चुका है।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कुल परियोजना लागत का अनुदान सहित अधिकतम ₹ पच्चीस लाख तक वित्त पोषण की सुविधा दी जा रही है।
- मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन एवं पलायन को रोकने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकास के उद्देश्य से "ग्रोथ सेन्टर की स्थापना" नामक योजना प्रस्तावित की गयी है।
- "ग्रोथ सेन्टर की स्थापना" योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता तथा प्रमाणिक उत्पादों की पहचान स्थापित कर कृषि, बागवानी या गैर कृषि उत्पाद अथवा आर्थिक गतिविधियों वाले भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुए तेजी से आर्थिक विकास को गति प्रदान की जाएगी और इसके तहत सभी तरह के खाद्य उत्पाद, बेमौसमी सब्जियों, मसालों, जड़ी–बूटी, औषधीय एवं सगन्ध पादप, शहद उत्पाद, पुष्प, प्राकृतिक रेशों (ऊन, रेशम, कण्डाली, भीमल आदि) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(23) **मेरी सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उच्च विकास दर पाने वाले शीर्षस्थ राज्यों में से है,** जो देश के तीव्र औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

- सरकार प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने हेतु प्रतिबद्ध है । इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का गठन किया गया है। अगले तीन वर्षों में एक लाख युवाओं को कौशल विकास योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पूँजीगत उपादान सहायता अधिकतम ₹ पच्चीस लाख एवं ब्याज उपादान सहायता छः प्रतिशत (अधिकतम ₹ पाँच लाख) प्रतिवर्ष प्रति इकाई अनुमन्य की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में दस लाख महिला उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्लास्टिक गुड्स आधारित उद्योगों के विकास, ऊन, शिल्प तथा प्राकृतिक रेशों के समुचित उपयोग हेतु आधुनिक डिजाइन/तकनीक में उच्च स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण देहरादून के डोईवाला एवं रानीपोखरी में संचालित किये जाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
- प्रदेश के हस्तशिल्प व हथकरघा संबंधित उत्कृष्ट उत्पादों को "हिमाद्रि" ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है।
- रोजगार सेवाओं को प्रभावी बनाने हेतु महत्वाकांक्षी नेशनल कैरियर सर्विस योजना आरम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य सेवायोजन कार्यालयों को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है।
- प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों को मॉडल कैरियर सेन्टर की तर्ज पर विकसित करते हुए इंटरलिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज योजना के अन्तर्गत उन्हें एन0सी0एस0 पोर्टल से जोड़े जाने एवं सेवायोजन कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है।
- रोजगार हेतु साक्षात्कार के माध्यम से तीन हजार एक सौ इकसठ अभ्यर्थियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया है।
- सरकार द्वारा राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

- सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत सिडकुल की सभी सेवाएं ऑनलाइन करते हुए सेवाओं का निस्तारण समयबद्ध रुप से किया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश के तहत सिडकुल के औद्योगिक आस्थान सितारगंज फेज–2 में मै0 इण्डियन ऑयल को लगभग तीस एकड़ भूमि बाटलिंग प्लांट हेतु आवंटित की गयी है। कम्पनी द्वारा उक्त प्लांट हेतु राज्य में लगभग ₹ एक सौ साठ करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
- नेपा लिमिटेड के कब्जे की हेमपुर स्थित आठ सौ तीन एकड़ भूमि को सिडकुल द्वारा वापस प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। शीघ्र ही उक्त भूमि के विकास की योजना तैयार कर औद्योगिक आस्थान विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- सिडकुल द्वारा सितारगंज में प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु डीपीआर तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।
- सिडकुल कानकोर लाजिस्टिक पार्क पंतनगर में विदेशी व्यापार हेतु परिसर में ही कस्टम क्लीयरेंस की व्यवस्था कर दी गई है।
- सरकार खनिज सम्पदा भण्डारों का अन्वेषण कर वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना एवं तकनीकी मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही है।
- ई–टेंडरिंग, सह नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। खनन से प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत खनिज न्यास का गठन किया गया है।

(24) मेरी सरकार ने वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य सत्रह हजार हेक्टेयर के सापेक्ष अठ्ठारह हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्न किया गया है।
- कैम्पा योजना में एक हजार एक सौ इकहत्तर जलकुण्ड, तीन हजार साठ पिरूल चेकडेम तथा एक हजार सात सौ हेक्टेयर वन क्षेत्रों में तीन लाख सत्तर हजार आठ सौ साठ कन्टूर नालियों के निर्माण कार्य पर लगभग ₹ पाँच सौ बीस लाख की धनराशि व्यय की गयी है।
- नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत एक सौ तिरपन हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य पर ₹ तीन सौ चौसठ लाख का व्यय किया गया है।

- जायका परियोजना के अन्तर्गत चयनित वन पंचायतों में लगभग तीन हजार चार सौ पचास चाल–खाल निर्माण, दस हजार दो सौ दस चेकडेम निर्माण, सोलह जल संग्रहण तालाबों का विकास तथा उपचार हेतु लिये गये समस्त क्षेत्रों में कन्टूर फरो बनाकर जल संरक्षण कार्य किया गया है।
- राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत एक सौ उन्नीस विभिन्न जल संरक्षण स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है।
- महिलाओं की वानिकी में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये महिला पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है तथा वन पंचायतों में पचास प्रतिशत सरपंच के पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं।
- चौड़ी पत्ती प्रजाति के ओक तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों हेतु देवदार प्रजाति का वृक्षारोपण कार्य पर्वतीय वन प्रभागों के अन्तर्गत सम्पन्न कराया गया है।
- ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य को व्यापक पैमाने पर किये जाने की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। राज्य में ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत लगभग दस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिशन का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में पर्यटन आधारित राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से देहरादून के निकट मालसी डियर पार्क को मिनी जू के रूप में विस्तारीकृत किया जा रहा है तथा हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय जू कम सफारी निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है।

(25) **प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में** सम्मिलित है। भारत सरकार की एकीकृत सूचना प्रबन्धन प्रणाली (आई0एम0आई0एस0) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कुल उन्तालीस हजार तीन सौ साठ बस्तियाँ हैं, जिनमें से भारत सरकार द्वारा निर्धारित चालीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानकानुसार इक्कीस हजार नौ सौ अड़सठ बस्तियाँ पूर्ण सेवित हैं तथा सत्रह हजार चार सौ बाईस बस्तियाँ आंशिक रूप से सेवित की जा रही हैं।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सत्तर योजनाएं पूर्ण कर तीन सौ पचास बसावटों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किया जा चुका है तथा वर्षान्त तक छिहत्तर योजनाएं पूर्ण कर पाँच सौ बाईस बसावटों को संतृप्त करने का लक्ष्य है।

- राज्य सरकार आम जनता की जन सुविधाओं तक पहुँच को सरल–सहज बनाने तथा सेवाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु संवेदनशील है। इस दृष्टि से उपभोक्ताओं को जल एवं सीवर संयोजनों की ऑनलाइन स्वीकृति तथा डेबिट/क्रेडिट/कैश कार्ड, नेट बैंकिग एवं तत्काल भुगतान सेवा (आई0एम0पी0एस0) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

(26) मेरी सरकार द्वारा वाणिज्यिक वादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत जिला देहरादून में एक वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है।

- सबके लिए शीघ्र एवं सुलभ न्याय सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्व के आलोक में विद्यमान विधियों का परीक्षण और उनमें सुधार करने तथा संविधान की भावनाओं एवं पर्वतीय राज्य की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए नई विधियों को तैयार करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग का गठन किया गया है।

(27) मेरी सरकार गरीब एवं वंचित वर्ग के नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दो सौ चौबीस ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का कार्य पूर्ण किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक घटक ए0एच0पी0 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में चौंतीस हजार ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।
- सम्पूर्ण राज्य में एक समान भवन उपविधि एवं निर्माण कार्यों में एक अधिनियम के तहत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया है।
- राज्य के चार जिले देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा नैनीताल के सम्पूर्ण भू–भाग को विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों के 200 मीटर की परिधि में आने वाले राजस्व गाँव तथा सम्पूर्ण स्थानीय निकाय के क्षेत्रों को विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

- सम्पूर्ण राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत मॉडल बिल्डिंग बॉयलाज तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है तथा जन आपत्ति आमंत्रण हेतु प्रक्रिया गतिमान है।
- देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश मेट्रोपोलिटन क्षेत्र हेतु मेट्रो रेल की डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है तथा देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश मेट्रोपोलिटन क्षेत्र हेतु मेट्रो रेल की सी0एम0पी0 बनाये जाने हेतु फर्म का चयन कर लिया गया है।

(28) **सरकार राज्य को ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्युत उत्पादन** बढ़ाने के लिए एवं विद्युत आपूर्ति में भी सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत राज्य में अवशेष अविद्युतीकृत ग्रामों में से अठ्ठावन अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं शेष छत्तीस ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- प्रदेश के अठ्ठाईस बड़े शहरों में विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 3 शहरों में कार्य अन्तिम चरणों में है। 36 छोटे शहरों में विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- "ऊर्जा मित्र" योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को एस0एम0एस0/कॉल/पुश नोटिफिकेशन्स द्वारा विद्युत कटौती की सूचना वास्तविक समय में दिये जाने हेतु उपभोक्ताओं को पंजीकृत कर लिया गया है।
- सौर ऊर्जा नीति में पाँच मेगावॉट तक के प्रोजेक्ट राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। सभी शासकीय कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों में एलईडी बल्ब एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
- ऊर्जा प्रदेश हेतु प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को एल0ई0डी0 बल्बों के वितरण की योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक उपभोक्ताओं को चौवालीस लाख एल0ई0डी0 बल्ब वितरित किये जा चुके हैं एवं चालू वर्ष में पचास लाख एल0ई0डी0 बल्ब वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

(29) **मेरी सरकार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी श्रम कानूनों के अन्तर्गत वादों का निस्तारण** कर उनको क्षतिपूर्ति, ग्रेच्यूटी, महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण एवं पुरूषों के समान पारिश्रमिक तथा

मातृका हितलाभ एवं कार्यस्थलों पर उनके यौन उत्पीड़न की शिकायतों के सम्बन्ध में विभिन्न औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा पारित निर्णयों का प्रतिपालन सुनिश्चित करने एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण व नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

- युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी "नेशनल कैरियर सर्विस" योजना प्रारम्भ की गयी है।
- श्रम कानूनों के अन्तर्गत वादों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। पंजीकरण, नवीनीकरण एवं उपसमन आदि स्रोतो से लगभग सात करोड़ की धनराशि राजस्व के रुप में प्राप्त हुई है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में छः नये चिकित्सालयों में से विकासनगर, मंगलौर, श्रीनगर, नई टिहरी एवं रामनगर में औषधालयों की स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।
- राज्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार से सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है तथा इसके लिए उचित स्थान पर भूमि के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आच्छादित बीमांकित लाभार्थियों के हितार्थ सचल औषधालयों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

(30) राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कुल पन्द्रह हजार सात सौ पैंतालीस ग्रामों में से बारह हजार एक सौ बीस ग्राम सड़कों से जोड़े जा चुके हैं तथा तीन हजार छः सौ पच्चीस ग्रामों के संयोजन हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यवाही गतिमान है।

- ट्राईबल सब प्लान में वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट प्राविधान लगभग अठ्ठारह करोड़ के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2017 तक सोलह करोड़ का व्यय किया गया है जिसके अन्तर्गत 12 किमी० का नव निर्माण एवं तीन किमी० पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों को यातायात हेतु पुनः खोल दिया गया है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपदा से प्रभावित मार्गों पर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए विशेषतः चारधाम यात्रा मार्गों को यातायात हेतु उपलब्ध कराया गया है। विगत वर्षों के सापेक्ष इस वर्ष यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- 'ऑल वेदर रोड' के अन्तर्गत तीन हजार तीन सौ इक्कीस सड़कों के कार्य स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष ₹ दो सौ तीस करोड़ के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा लगभग ₹ तीन हजार एक सौ करोड़ के कार्यों की निविदायें प्राप्त हैं। इन कार्यों हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बहत्तर के अन्तर्गत मोहकमपुर, देहरादून में चार लेन सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे माह दिसम्बर तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
- जिला टिहरी में डोबरा चांटी सेतु निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य माह जुलाई तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- देहरादून शहर में चार लेन रिंग रोड़, जिसकी लम्बाई एक सौ पन्द्रह कि0मी0, अनुमानित लागत ₹ एक हजार चार सौ दस करोड़ है, के निर्माण हेतु शासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
- हल्द्वानी नगर में चालीस कि0मी0 चार लेन रिंग रोड निर्माण हेतु लगभग ₹ एक सौ सत्तावन करोड़ की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, कन्सलटेन्सी का कार्य प्रगति पर है।
- अल्मोड़ा शहर में धारानौला से लोअर माल रोड़ को जोड़ने हेतु सुरंग के निर्माण कार्य की डी0पी0आर0 एवं नियोजन का कार्य प्रगति पर है।
- मार्गों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत नये वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के कार्यों की योजना माह दिसम्बर से प्रारम्भ कर दी गई है।
- वित्तीय मितव्ययिता के दृष्टिगत मार्गों का रख–रखाव प्रचलित सामान्य नवीनीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त क्रैक सीलिंग विधि द्वारा प्रारम्भ किया गया है।
- पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के दृष्टिगत ट्रेडिंग मशीन के प्रयोग से प्रथम बार वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जिसकी गुणवत्ता स्तरीय एवं स्थायित्वपूर्ण पाई गयी है।
- इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत लोकल मैटीरियल के साथ–साथ सॉयल स्टैबलाईजेशन का प्रयोग पौड़ी, ऊधमसिंह नगर एवं चमोली जिलों में किया जा रहा है।

- सरकार द्वारा कृषकों को ₹ 1.00 लाख की सीमा तक का ऋण 2 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित कृषि पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए स्वैच्छिक चकबंदी को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- न्याय पंचायत स्तर पर कृषि में महिला श्रम को कम करने तथा कृषि में यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रत्येक न्याय–पंचायत पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में न्याय पंचायत स्तर पर दो सौ मशीनरी बैंक स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है।
- कृषि, उद्यान, जड़ी–बूटी एवं जैविक कृषि को पर्यटन से जोड़ने हेतु कार्य योजना बनायी जा रही है।
- सरकार द्वारा 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने एवं संबंधित समन्वय स्थापित करने, उन्नत बीज, यंत्र, दवाईयों की समुचित व्यवस्था व नवीनतम तकनीकी उपलब्ध कराने एवं प्रदेश को जैविक खेती के रूप में विकसित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
- कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु अधिक पैदावार वाली किस्मों, परम्परागत बीज, फल पट्टी विकसित करने, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्थापित करने, पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- सरकार द्वारा किसान पोर्टल पर कृषकों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- सरकार स्किल डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत किसानों एवं बेरोजगार नवयुवकों के लिए मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सब्जी पौध उत्पादन, दुधारू पशुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है एवं फल पट्टी विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।
- हैचरी की सहायता से मत्स्य पालन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।
- स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंतनगर विश्वविद्यालय को स्वच्छतम उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- विश्व बैंक एवं यूरोपीय यूनियन के वित्त पोषण से ₹ आठ सौ छियान्वे करोड़ व्यय कर प्रदेश के दो सौ उनहत्तर सूक्ष्म जलागमों के नौ हजार नौ सौ उनसठ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में

परियोजना कार्य किये गये हैं। विभागीय योजनाओं, जलागम विकास की योजनाओं का निर्माण व उनका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

- सरकार पशुपालन व्यवसाय में वर्णसंकर और स्वदेशी नस्लों के उन्नयन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल कर रही है।
- सरकार पंजीकृत "बद्री नस्ल" की गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु बद्री नस्ल गायों का फील्ड परफारमेंस रिपोर्ट तैयार करा रही है। सरकार पशुपालकों के पशुओं के नस्ल सुधार का प्रयास कर रही है।
- सरकार निराश्रित, अशक्त एवं आवारा पशुओं को उचित शरण स्थली प्रदान करने हेतु गौ सदन संचालक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रही है एवं कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- सरकार द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों की दस सौ सैंतालिस महिला सदस्य को "गंगा गाय महिला डेयरी योजना" के अन्तर्गत दुधारू पशुओं के क्रय हेतु ₹ सत्ताईस हजार प्रति गाय की दर से राज्य सहायता दी जा रही है।
- सरकार दुग्ध सहकारी समितियों के सैंतालिस हजार दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त चार रूपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा रही है।

(32) सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य शीघ्र गन्ना प्रजाति का ₹ तीन सौ छब्बीस प्रति कुन्तल एवं सामान्य प्रजाति का ₹ तीन सौ सोलह प्रति कुन्तल दिया जा रहा है। गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

- चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर द्वारा उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की पौधशालाएं विकसित की जा रही हैं।
- विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा राज्य स्तरीय, अन्तर्राज्य स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से गन्ना कृषकों एवं फील्ड कर्मचारियों को नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(33) आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के अन्तर्गत अधिकांश विभागों की शासकीय सम्पत्तियां हस्तान्तरित हो चुकी हैं। शेष विभागों की सम्पत्तियाँ हस्तांतरित होने की कार्यवाही गतिमान है।